



Daily करेंट अफेयर्स

» 25 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. MoHUA ने मानसून 2025 से पहले 'सफाई अपनाओ, बीमार भगाओ (SABB)' अभियान शुरू किया।



मानसून से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने और शहरी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने हाल ही में 23 जुलाई, 2025 को राष्ट्रव्यापी 'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ (SABB)' अभियान शुरू किया। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य व्यापक स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0 के तहत नालियों की सफाई और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

- SABB अभियान, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का मानसून की तैयारी का अभियान है जो विशेष रूप से शहरों और कस्बों में नालों की सफाई, स्वच्छता संवर्धन और जनसहभागिता पर केंद्रित है। यह शहरी स्थानीय निकायों (ULB), नागरिकों, स्कूली बच्चों और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। इसका उद्देश्य बारिश के मौसम में नालियों की सफाई और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य जोखिमों और वेक्टर जनित बीमारियों को कम करना है।

- SBM-U 2.0 के एक भाग के रूप में, SABB अभियान छह "स्वच्छता मंत्रों" को सुदृढ़ करता है: स्वच्छ हाथ, स्वच्छ घर, स्वच्छ पड़ोस, स्वच्छ

शौचालय, स्वच्छ नालियाँ और स्वच्छ सार्वजनिक स्थान। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को सोशल मीडिया अभियानों, सड़क रैलियों और शहरी क्षेत्रों में संवादात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों में स्वच्छता संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रचारित किया जा रहा है।

- विभिन्न राज्यों ने SABB अभियान में अभिनव रूप से भाग लिया है। बिहार में, पटना नगर निगम (PMC) ने "मैनहोल एम्बुलेंस" शुरू कीं - विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहन जो मैनहोल का त्वरित और सुरक्षित रखरखाव करते हैं। दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 'पिकथॉन' का आयोजन किया, जिसमें 400 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की बालिका कैडेटों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई।

Key Points:-

(i) महाराष्ट्र में, नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने ज्ञानदीप सेवा मंडल हाई स्कूल के सहयोग से 600 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल करते हुए एक स्वच्छता रैली का आयोजन किया।

(ii) तेलंगाना में जलभराव को रोकने और सार्वजनिक स्वच्छता में सुधार के लिए अपशिष्ट पृथक्करण और नालियों की सफाई के लिए घर-घर अभियान जैसे कई पहल शुरू किए गए।

(iii) आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानसून में स्वच्छता संबंधी यह सक्रिय पहल, स्वच्छ भारत को केवल एक अभियान न बनाकर, बल्कि एक दैनिक अभ्यास में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक जन भागीदारी, विशेष रूप से स्कूलों, शहरी संस्थानों और स्थानीय सरकारों की भागीदारी के साथ, SABB स्वच्छ और रोगमुक्त शहरों के लिए एक जन-नेतृत्व वाला आंदोलन बन रहा है।

2. भारत ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत स्किल नेक्स्ट 2025 के शुभारंभ के साथ कौशल भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया।



जुलाई 2025 में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 'भारत स्किल नेक्स्ट 2025' नामक एक भव्य प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन करके कौशल भारत मिशन के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में परिवर्तनकारी कौशल पहलों का शुभारंभ और कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

- केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और अगले दशक के लिए भारत के कौशल परिवर्तन रोडमैप के अनुरूप प्रमुख लॉन्चों का नेतृत्व किया।

- सम्मेलन में इंडियास्किल्स 2025-26 परिचालन दिशानिर्देश और पंजीकरण पोर्टल, SOAR प्लेटफॉर्म (कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता के लिए कौशल), और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा कौशल वर्सेस डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल (DEP) सहित प्रमुख पहलों का अनावरण किया गया।

Key Points:-

(i) MSDE और फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर

हस्ताक्षर किए गए, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा में भारत के रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

(ii) इनक्यूबेशन और उन्नत कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) के साथ अतिरिक्त समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया, जिनमें बेंगलुरु (DST योजना के तहत एसएलएन प्रौद्योगिकी के साथ) और मुंबई (ICICI फाउंडेशन के साथ) शामिल हैं।

(iii) सार्वजनिक-निजी कौशल विकास सहयोग को बढ़ाने के लिए PMKVY के तहत माइक्रोसॉफ्ट, HCL, डिकसन टेक्नोलॉजीज और अपोलो मेडस्किल्स जैसे प्रमुख भारतीय उद्योग के खिलाड़ियों के साथ-साथ IIT पटना, IIIT ऊना, IIT हैदराबाद, NIT अगरतला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्रीय निदेशालयों (RDSDEs) द्वारा कई फ्लेक्सी-MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

3. भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो 2030 के लक्ष्य से पहले ही पार हो जाएगा।



2025 की शुरुआत में, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण अनुपात (E20) को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है - जो कि 2030 की मूल समय सीमा

से पांच से छह साल पहले है। इस उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 23 जुलाई 2025 को ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) राउंड-IX हस्ताक्षर समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान की।

- जून 2021 में, सरकार ने अपने इथेनॉल मिश्रण रोडमैप को संशोधित किया—इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत 20% मिश्रण लक्ष्य को 2030 से इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 तक स्थानांतरित कर दिया। 2022 की शुरुआत तक, भारत पहले ही 10% मिश्रण के आंकड़े को पार कर चुका था, और 2024 के अंत तक लगभग 19.6% तक पहुँच गया था।

- इस उपलब्धि से कच्चे तेल के आयात में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय बचत हुई है—लगभग ₹1.36 लाख करोड़, जो कि ₹1.5 लाख करोड़ तक पहुँच सकती है। इससे ग्रामीण आय में भी वृद्धि हुई है: डिस्टिलरी को ₹1.18 लाख करोड़ का भुगतान किया गया और इथेनॉल की बढ़ती माँग से लाभान्वित होकर किसानों को ₹1.96 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से लगभग 698 लाख टन CO₂ उत्सर्जन से बचा जा सका।

- भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता 2025 के मध्य तक लगभग 1,685 करोड़ लीटर तक बढ़ जाएगी, जो कि विस्तारित बुनियादी ढाँचे और फीडस्टॉक विविधीकरण—गन्ने, मक्का और अतिरिक्त चावल से प्राप्त—के बल पर संभव होगी। उदाहरण के लिए, मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इथेनॉल के लिए रिकॉर्ड 5.2 मिलियन मीट्रिक टन एफसीआई चावल आवंटित किया गया।

Key Points:-

(i) सरकार के रोडमैप के अनुसार, घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए ESY 2025-26 तक प्रतिवर्ष लगभग 1,016 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता

होगी - जिसे उत्पादन आंकड़ों के आधार पर सही ढंग से मापा जाएगा।

(ii) E20 की सफलता के बाद, सरकार ब्राज़ील जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप 27% (E27) तक त्वरित सम्मिश्रण लक्ष्यों पर विचार कर रही है। नीति आयोग के अधीन एक समिति 20% से आगे सम्मिश्रण बढ़ाने की व्यवहार्यता और पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारी का मूल्यांकन कर रही है।

(iii) मंत्री महोदय के अनुसार, भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन दृष्टिकोण में, जिसका लक्ष्य 7-10 ट्रिलियन डॉलर की स्थायी अर्थव्यवस्था बनाना है, इथेनॉल मिश्रण, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के साथ एक प्रमुख स्तंभ है। भारत अब दुनिया भर में इथेनॉल मिश्रण करने वाले शीर्ष देशों में शामिल है, और ब्राज़ील भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मानक है।

INTERNATIONAL

1. भारत और न्यूज़ीलैंड ने नई दिल्ली में FTA वार्ता का दूसरा दौर पूरा किया और तीसरा दौर सितंबर 2025 के लिए निर्धारित किया गया।



भारत और न्यूज़ीलैंड ने हाल ही में नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जो 14 से 25 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। वार्ता में वस्तुओं,

सेवाओं, निवेश, व्यापार सुविधा, उत्पत्ति के नियमों और व्यापार में तकनीकी बाधाओं सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिससे सितंबर में न्यूजीलैंड में होने वाले तीसरे दौर के लिए मंच तैयार हो गया।

- मार्च 2025 में FTA वार्ता की बहाली 2015 से एक दशक के लंबे अंतराल के बाद हुई। दूसरे दौर की वार्ता, जो 12 दिनों तक चली, मई की शुरुआत में हुए प्रारंभिक विचार-विमर्श के आधार पर शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच एक संतुलित, व्यापक और द्वंद्वेशी व्यापार समझौते को तैयार करना है।

- ये चल रही वार्ताएँ मज़बूत आर्थिक गति को दर्शाती हैं: भारत-न्यूजीलैंड व्यापारिक व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 48.6% की वृद्धि है। यह वृद्धि एक व्यापक व्यापार समझौते के संभावित लाभों को रेखांकित करती है।

- वार्ता में प्रमुख चुनौतियों में डेयरी बाज़ार तक पहुँच शामिल है - जो भारत के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र है। न्यूजीलैंड ने भारतीय डेयरी, मांस और वाइन बाज़ारों तक बेहतर पहुँच की माँग की है। इस बीच, भारत अपने आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और सेवा उद्योगों के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच की माँग कर रहा है, जो आवश्यक रियायतों के जटिल संतुलन को उजागर करता है।

Key Points:-

(i) भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया, जबकि न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने न्यूजीलैंड की ओर से प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी भागीदारी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता में तेज़ी लाने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए उच्चतम स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(ii) एक सफल मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आपूर्ति

श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाकर, निर्यात (जैसे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और झींगा) में विविधता लाकर, और निवेश एवं सेवा सहयोग के लिए मज़बूत अवसर पैदा करके दोनों राष्ट्रमंडल भागीदारों के बीच व्यापार में बदलाव लाएगा। नियोजित अंतर-सत्रीय वर्चुअल बैठकों का उद्देश्य न्यूजीलैंड में सितंबर 2025 के दौर से पहले गति बनाए रखना है।

2. जुलाई 2025 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुँच गया तथा सिंगापुर सूची में शीर्ष पर है।



जुलाई 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 8 पायदान चढ़कर 77वें स्थान पर पहुँच गया, जो जनवरी 2025 में 85वें स्थान पर था। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा 22 जुलाई 2025 को जारी यह सूचकांक भारत की बेहतर वैश्विक गतिशीलता और मज़बूत राजनयिक संबंधों पर प्रकाश डालता है, जो वीज़ा-मुक्त पहुँच के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- भारत अब दुनिया भर के 59 देशों में वीज़ा-मुक्त या आगमन पर वीज़ा सुविधा का लाभ उठा सकता है, जबकि पिछले सूचकांक में यह संख्या 57 थी। इस सुधार के साथ, भारत अब बुर्किना फ़ासो, सेनेगल और कोटे डी आइवर के साथ 77वें स्थान पर है।

● यह प्रगति सूचकांक के इस संस्करण में दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि है और यह भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा सुगम बनाए गए बेहतर द्विपक्षीय यात्रा समझौतों के अनुरूप है।

● सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 227 में से 193 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुँच प्रदान करके शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जिससे यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। जापान और दक्षिण कोरिया 190 देशों तक पहुँच के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। शीर्ष तीन में एशियाई देशों का मजबूत प्रदर्शन उनके वैश्विक प्रभाव और मजबूत राजनयिक संबंधों को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) वैश्विक सूचकांक में तीसरा स्थान संयुक्त रूप से सात यूरोपीय संघ (EU) देशों - जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, फ़िनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड - को प्राप्त है, जिनमें से प्रत्येक 189 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्वीडन शामिल हैं, जिनकी 188 गंतव्यों तक पहुँच है, जो पासपोर्ट गतिशीलता में यूरोप की निरंतर मजबूती को दर्शाता है।

(ii) हाल के वर्षों में भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। 2023 में, भारत 56 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच के साथ 84वें स्थान पर था। जनवरी 2025 तक, यह रैंक थोड़ी गिरकर 85वें स्थान पर आ गई, लेकिन जुलाई 2025 में 77वें स्थान पर पहुँचना हाल के द्विपक्षीय प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है। मेडागास्कर, बोलीविया और रवांडा जैसे देशों ने हाल ही में भारत को अपनी वीजा-मुक्त या आगमन पर वीजा सूची में शामिल किया है, जिससे भारत का वैश्विक गतिशीलता स्कोर बढ़ा है।

(iii) हेनले पासपोर्ट सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय वायु

परिवहन संघ (IATA) के विशिष्ट आँकड़ों का उपयोग करके संकलित किया जाता है और 227 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त या आगमन पर वीजा पहुँच के आधार पर 199 पासपोर्टों को रैंक करता है। किसी देश की यात्रा स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इसे व्यापक रूप से एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। 2025 के सूचकांक में भारत का स्थान बढ़ने से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे और वैश्विक मंच पर उसकी राजनयिक उपस्थिति मज़बूत होगी।

BANKING & FINANCE

1. ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा SBI को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया।



ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। यह पुरस्कार उपभोक्ता बैंकिंग में ग्राहक-केंद्रित नवाचार और उत्कृष्टता के वैश्विक मानक को दर्शाता है। SBI के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी 18 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन DC में IMF/विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित होने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्राप्त करेंगे।

● SBI का चयन ग्लोबल फाइनेंस के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित था, जिसमें कॉर्पोरेट वित्त

अधिकारियों, विश्लेषकों और वैश्विक बैंकिंग विशेषज्ञों से प्राप्त फीडबैक शामिल था। मानदंडों में ग्राहक जुड़ाव, डिजिटल परिवर्तन, पहुँच, वित्तीय मज़बूती और नवाचार पर ज़ोर दिया गया।

- अध्यक्ष सी.एस. शेटी ने ज़ोर देकर कहा कि ग्राहक अनुभव SBI की विकास रणनीति का केंद्रबिंदु बना हुआ है। उन्होंने सरलीकृत ऑनबोर्डिंग, स्थानीय भाषा में वॉइस बैंकिंग, 24/7 डिजिटल सहायता और विविध वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के लिए डिज़ाइन की गई AI-संचालित हाइपर-पर्सनलाइज़्ड पेशकशों जैसी पहलों पर प्रकाश डाला।

- यह पुरस्कार SBI के मज़बूत पैमाने और प्रदर्शन को रेखांकित करता है। मार्च 2025 तक, SBI का जमा आधार ₹53.82 लाख करोड़ से अधिक है, जिसमें ₹42.20 लाख करोड़ से अधिक के अग्रिम और ₹8.3 लाख करोड़ का गृह ऋण पोर्टफोलियो शामिल है, जो भारतीय बंधक बाजार का 27.3% है। SBI देश भर में 22,542 शाखाओं और 63,580 से अधिक ATMs के माध्यम से 52 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) SBI का डिजिटल परिवर्तन महत्वपूर्ण रहा है: लगभग 92% लेन-देन अब डिजिटल हैं, जो इसके प्रमुख योनो ऐप के कारण संभव हुआ है, जिसके लगभग 8.13 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, और अकेले वित्त वर्ष 2025 में 3.7 मिलियन उपयोगकर्ता और जुड़ेंगे। इस डिजिटल पहल ने राजस्व और लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

(ii) वैश्विक स्तर पर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पुरस्कार 150 से अधिक देशों और 11 क्षेत्रों में बैंकिंग उत्कृष्टता का मूल्यांकन करते हैं। ग्लोबल फ़ाइनेंस मात्रात्मक प्रदर्शन संकेतकों और गुणात्मक विशेषज्ञ इनपुट, दोनों का उपयोग करके बैंकों का मूल्यांकन करता है—जो इसे ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग में नेतृत्व के

लिए एक विश्वसनीय मानक बनाता है।

(iii) SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 के रूप में मान्यता मिलना न केवल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच इसके नेतृत्व को उजागर करता है, बल्कि विश्व मंच पर इसकी उपस्थिति को भी मज़बूत करता है, जो समावेशी वित्त, स्केलेबल डिजिटल बुनियादी ढांचे और वित्तीय नवाचार में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने 31 मार्च, 2025 तक ₹1.62 ट्रिलियन मूल्य के 1,629 विलफुल डिफॉल्टर मामलों की सूचना दी।



केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक खुलासे के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने 1,629 विलफुल डिफॉल्टर मामलों की पहचान की है, जिनका कुल बकाया ₹1.62 ट्रिलियन है। ये ऋण ऐसी संस्थाओं से हैं जो चुकाने में सक्षम हैं, लेकिन जानबूझकर भुगतान से बच रही हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र की सेहत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

- संकट के जवाब में, सरकार ने कई कानूनी और प्रशासनिक वसूली तंत्र शुरू किए हैं, जिनमें SARFAESI अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत कार्रवाई, और CIBIL और

एक्सपीरियन जैसे क्रेडिट ब्यूरो के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटीकरण शामिल है।

● यह मुद्दा विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धीमी जमा वृद्धि और बढ़ते ऋण जोखिम के साथ मेल खाता है - ऐसे कारक जो बैंकों की वित्तीय झटकों को सहन करने की क्षमता को कम करते हैं।

Key Points:-

(i) तुलना के तौर पर, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने पहले (2020 में) ₹1.47 लाख करोड़ बकाया वाले 2,426 विलफुल डिफॉल्टर खातों की सूची जारी की थी, जो लंबे समय से चली आ रही प्रणालीगत समस्याओं को रेखांकित करता है।

(ii) शीर्ष संस्थानों पर सबसे अधिक बोझ है: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पास ही हजारों करोड़ रुपये की जानबूझकर चूक करने वाले खातों की संख्या सैकड़ों में है। अन्य प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी उच्च स्तर के गैर-निष्पादित बकायों की रिपोर्ट दी है।

(iii) वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़े रिपोर्टिंग मानदंडों की सिफारिश की है: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े कर्जदारों के पासपोर्ट प्राप्त करने होंगे, डिफॉल्टरों का प्रोफाइल प्रकाशित करना होगा, लुकआउट सर्कुलर जारी करना होगा, तथा जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को ऋण या पूंजी बाजार तक पहुंचने से रोकना होगा।

3. पेपाल ने NIPL और वैश्विक भुगतान प्रदाताओं के साथ साझेदारी में 'पेपाल वर्ल्ड' लॉन्च किया।



23 जुलाई 2025 को, अमेरिका की एक प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी, पेपाल ने भारत की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और तीन अन्य वैश्विक प्रदाताओं के साथ साझेदारी में एक नए सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म, 'पेपाल वर्ल्ड' के शुभारंभ की घोषणा की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के बीच निर्बाध एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन को सक्षम किया जा सके।

● अपने प्रारंभिक चरण में, पेपाल वर्ल्ड ने चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है।

● इनमें NIPL (NPCI की अंतरराष्ट्रीय शाखा और UPI का संचालक), ब्राज़ील की मर्काडो पेगो, चीन की टेनपे ग्लोबल (वेक्सिन पे) और पेपाल की अमेरिकी सहायक कंपनी वेनमो शामिल हैं। इन सहयोगों का उद्देश्य भारतीय UPI -आधारित लेनदेन और डिजिटल वॉलेट की वैश्विक व्यापारी स्वीकृति को सीमा पार सरल बनाना है।

● यह पहल भारतीय उपयोगकर्ताओं को PayPal स्वीकार करने वाले अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यापारियों को भुगतान के लिए अपने UPI क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे भारत के रीयल-टाइम भुगतान बुनियादी ढांचे की वैश्विक उपयोगिता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह UPI के वैश्वीकरण और सीमा पार डिजिटल वाणिज्य के लिए पारंपरिक बैंकिंग पर

निर्भरता कम करने की भारत की महत्वाकांक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Key Points:-

(i) पेपाल वर्ल्ड कई स्थानीय भुगतान प्रणालियों, डिजिटल वॉलेट और बहु-मुद्रा उपयोग का समर्थन करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और धन प्रेषण आसान हो जाते हैं। यह एक उपभोक्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ भारतीय ग्राहक यूपीआई के बुनियादी ढाँचे द्वारा समर्थित परिचित स्थानीय भुगतान विधियों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर भुगतान कर सकते हैं।

(ii) नया समाधान सुव्यवस्थित व्यापारी एकीकरण पर भी केंद्रित है। इस प्रणाली के साथ, दुनिया भर के व्यापारी कई भुगतान गेटवे को शामिल किए बिना व्यापक ग्राहक आधार से जुड़ सकेंगे। इससे ऑनबोर्डिंग की जटिलता में भारी कमी आ सकती है और सीमा पार ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिल सकता है।

(iii) तकनीकी दृष्टिकोण से, 'पेपैल वर्ल्ड' क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह अगली पीढ़ी की गतिशील भुगतान सुविधाओं, जैसे स्टेबलकॉइन और प्रोग्रामेबल भुगतानों के लिए समर्थन, का समर्थन करने के लिए उच्च उपलब्धता, कम विलंबता और वैश्विक मापनीयता सुनिश्चित करता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर निवेश माहौल का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2026 के GDP पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है।



जुलाई 2025 में, फिच ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 6.3% कर दिया है, जो दिसंबर 2024 में किए गए 6.6% के अपने पहले के अनुमान से 30 आधार अंक कम है।

● इंडिया रेटिंग्स ने इस रेटिंग में गिरावट के प्रमुख कारणों के रूप में घरेलू और वैश्विक चुनौतियों का हवाला दिया है, जिनमें अमेरिका द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी और कमजोर निवेश माहौल शामिल हैं। रेटिंग में गिरावट के बावजूद, मुद्रास्फीति में कमी और अच्छी बारिश के अनुमान जैसे सकारात्मक कारकों से आगामी वित्तीय वर्ष में आर्थिक प्रभाव कम होने की उम्मीद है।

● एजेंसी ने महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया है, जिनमें अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ वृद्धि से बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताएं शामिल हैं, जिससे कई अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं तथा कमजोर निवेश माहौल भी शामिल है, जिससे भारत में निजी और संस्थागत निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है।

● हालाँकि, अपेक्षित मौद्रिक सहजता, मुद्रास्फीति में अपेक्षा से अधिक गिरावट और 2025 के लिए सामान्य से बेहतर मानसून पूर्वानुमान जैसी अनुकूल परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। इंड-रा ने

कहा कि ये सकारात्मक घटनाक्रम वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।

Key Points:-

- (i) खुदरा मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, Ind-Ra ने वित्त वर्ष 26 के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 3% कर दिया है, जो पहले के 4.3% के अनुमान से कम है। यह संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति के जून 2025 में घटकर 2.1% रह जाने से समर्थित है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4% के लक्ष्य से काफी नीचे है।
- (ii) निजी उपभोग में लगातार वृद्धि की उम्मीद है, और Ind-Ra का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में साल-दर-साल (YoY) 6.9% की वृद्धि होगी। यह अनुमान मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के बाद उपभोक्ता धारणा में सुधार को दर्शाता है।
- (iii) निवेश मांग के संदर्भ में, सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) के अब वित्त वर्ष 26 में 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले के 7.2% के अनुमान से कम है। इंड-रा ने कहा कि यह गिरावट वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के बीच कॉर्पोरेट और बुनियादी ढाँचा निवेशकों के बीच सतर्कता की भावना का संकेत है।

2. ADB ने व्यापार अनिश्चितता और कमजोर निवेश का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2025 के GDP विकास अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया।



11-12 दिसंबर 2024 को, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमानों को संशोधित किया, और वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने पूर्वानुमान को पहले के 7% से घटाकर 6.5% कर दिया। यह समायोजन धीमे निजी निवेश, सीमित आवास मांग और वैश्विक व्यापार तनावों से जुड़ी चिंताओं को दर्शाता है।

- ADB ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 5.4% की तीव्र गिरावट का हवाला दिया है—जो सात तिमाहियों के निचले स्तर पर है, जिसकी वजह विनिर्माण उत्पादन में मंदी (सालाना आधार पर 3.6%), असुरक्षित ऋणों पर सख्त विवेकपूर्ण मानदंड और सरकारी पूंजीगत व्यय में कमी है। सेवाओं (7.1%) और कृषि (3.5%) में मज़बूत वृद्धि के बावजूद, कुल मिलाकर गति उम्मीदों से कम रही।

- जुलाई 2025 के अपने एशियाई विकास परिदृश्य में, एडीबी ने भारत के वित्त वर्ष 26 के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.5% (6.7% से) कर दिया, तथा इसमें वृद्धि में प्रमुख बाधाओं के रूप में उच्च अमेरिकी टैरिफ, जारी नीति अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग - विशेष रूप से निर्यात बाजारों में - की ओर इशारा किया।

- ADB ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 4.7% पर बरकरार रखते हुए, खाद्य और ऊर्जा की घटती कीमतों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026 के अपने अनुमान को घटाकर 3.8%

कर दिया। अनुमान यह मानता है कि कम मुद्रास्फीति 2026 की शुरुआत में और अधिक मौद्रिक ढील के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करेगी।

Key Points:-

(i) डाउनग्रेड के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण पुनरुद्धार, मज़बूत उपभोक्ता मांग और सेवा क्षेत्र की मज़बूत गतिविधियों के कारण वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 7.4% की वृद्धि के साथ लचीलापन दिखाया। ADB का मानना है कि ये बुनियादी कारक आगामी तिमाहियों में क्रमिक सुधार में सहायक हो सकते हैं।

(ii) ADB ने वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिसे वित्त वर्ष 2027 के लिए संशोधित कर 7.0% कर दिया है। यह अनुमान निवेश प्रवाह में स्थिरता, अनुकूल मानसून से प्रेरित कृषि क्षेत्र में मजबूती और निरंतर घरेलू मांग को देखते हुए लगाया गया है। पूर्वानुमान में राजकोषीय चुनौतियों के कम होने के बाद निजी निवेश में सुधार के साथ-साथ मजबूत पूंजीगत व्यय की भी उम्मीद जताई गई है।

MOUs and Agreement

1. मारुति सुजुकी ने भारत भर में ऑटो और मोबिलिटी स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए DPIIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



23 जुलाई 2025 को, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य ऑटोमोबाइल निर्माण और मोबिलिटी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत मारुति सुजुकी के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँच बनाने में मदद मिलेगी।

● मारुति सुजुकी यह सुनिश्चित करेगी कि चयनित स्टार्टअप उसके चार प्रमुख नवाचार प्लेटफार्मों—एक्सीलरेटर, इनक्यूबेशन, मोबिलिटी चैलेंज और नर्चर—में भाग ले सकें। ये कार्यक्रम संरचित मार्गदर्शन, उद्योग की अंतर्दृष्टि और बाजार-तैयार तकनीकों के विकास और सत्यापन के लिए वास्तविक दुनिया के परीक्षण बुनियादी ढांचे तक पहुँच प्रदान करते हैं। यह सहयोग मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, दोनों के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ एक गहन संरेखण को दर्शाता है।

● DPIIT ढांचे के तहत स्वीकृत स्टार्टअप्स को एक व्यापक नवाचार नेटवर्क—इन्क्यूबेटर, एक्सेलरेटर, निवेशक और संभावित कॉर्पोरेट साझेदार—से जोड़ा जाएगा ताकि वे आशाजनक समाधानों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा सकें। इससे ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में प्रारंभिक चरण के विचार और

व्यावसायीकरण के बीच पारंपरिक अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

Key Points:-

(i) 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स की स्क्रीनिंग, लगभग 150 को शामिल करने और 28 को पूर्व समूहों में शामिल करने के साथ, मारुति सुजुकी ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

(ii) DPIIT के साथ यह समझौता ज्ञापन स्टार्टअप्स को मजबूत स्केलेबिलिटी मार्ग और वास्तविक विनिर्माण सत्यापन वातावरण तक सीधी पहुंच प्रदान करके अगली पीढ़ी के औद्योगिक और गतिशीलता नवाचार में भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए तैयार है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. ACC द्वारा अजय सेठ को 3 वर्ष के लिए IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।



भारत सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को 24 जुलाई, 2025 से प्रभावी तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी।

● अजय सेठ की नियुक्ति, पूर्व IRDAI अध्यक्ष देबाशीष पांडा का कार्यकाल पूरा होने के बाद मार्च 2025 में होने वाली शीर्ष रिक्ति को भरती है। नियमों के अनुसार, यह कार्यकाल तीन वर्ष या श्री सेठ की 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा। यह नियुक्ति बीमा विनियमन क्षेत्र में अनुभवी नेतृत्व पर सरकार के फोकस को पुष्ट करती है।

● यह चयन कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) की सिफारिशों के आधार पर किया गया।

● यह समिति भारत के वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख नियामक पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए ज़िम्मेदार है। FSRASC की अनुशंसा पर ACC द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया।

Key Points:-

(i) अजय सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। उन्हें वित्त, बुनियादी ढाँचे और नियामक नीति के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। इस पद पर आने से पहले, उन्होंने 2021 से जून 2025 तक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव के रूप में कार्य किया।

(ii) अपनी आर्थिक मामलों के विभाग की भूमिका के अलावा, सेठ को मार्च 2025 में तुहिन कांता पांडे के पद छोड़ने के बाद राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। वे वित्तीय बाज़ार विनियमन से संबंधित उच्च-स्तरीय पैनल का भी हिस्सा थे और SEBI तथा अन्य नियामकों के साथ उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी समान थीं।

(iii) अजय सेठ के कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक वित्त, शहरी विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का उल्लेखनीय अनुभव शामिल है। उन्होंने एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम किया है। उनके योगदान को 2013 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के

लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

IMPORTANT DAYS

1. 25 जुलाई 2025 को अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।



25 जुलाई 2025 को, संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर नामित दिवस है, जिसे पहली बार अगस्त 2024 में महासभा के प्रस्ताव 78/323 के माध्यम से अपनाया गया था। यह दुनिया भर में अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के अद्वितीय योगदान और चुनौतियों को मान्यता देता है।

- यह दिवस अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक (2025-2034) के अनुरूप है और इसका उद्देश्य नस्ल, लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर व्याप्त भेदभाव के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह न्याय, सम्मान और विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीति निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है।

- यह दिवस अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली प्रणालीगत असमानताओं - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित

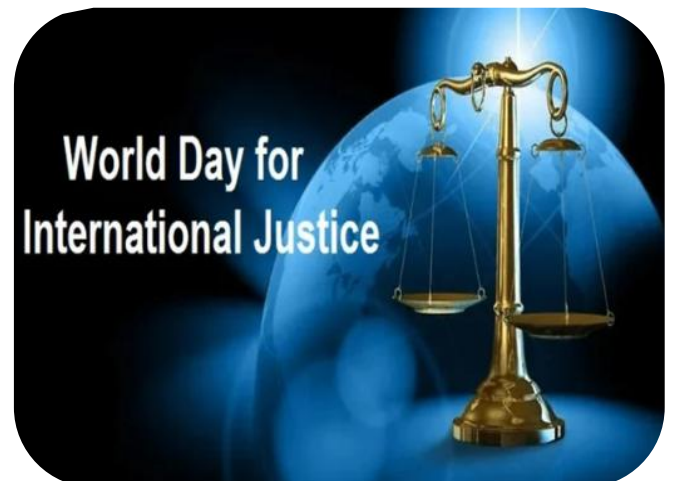
पहुंच - पर प्रकाश डालता है, साथ ही कानून, राजनीति, संस्कृति, विज्ञान, कला और सक्रियता जैसे क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है।

Key Points:-

(i) संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ और मानवाधिकार संस्थाएँ ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए नस्ल और लिंग के आधार पर अलग-अलग आँकड़े, सकारात्मक कार्रवाई और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देती हैं। नेतृत्व, शिक्षा और कानूनी न्याय पर केंद्रित सशक्तिकरण कार्यक्रमों को समानता के मार्ग के रूप में रेखांकित किया जाता है।

(ii) इस दिन, सरकारें, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज और समुदाय अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों की आवाज को बुलंद करने, उनके लचीलेपन का जश्न मनाने और नस्लवाद, लिंगवाद, विदेशी घृणा और हाशिए पर डालने को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता की मांग करने के लिए सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यशालाएँ और पैनल चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

2. 25 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस का उद्घाटन किया जाएगा, जो वैश्विक न्याय सुधार में एक मील का पत्थर साबित होगा।



4 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव A/RES/79/266 को सर्वसम्मति से अपनाने के बाद,

25 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने न्यायिक कल्याण के लिए अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 70 से अधिक देशों द्वारा सह-प्रायोजित, यह प्रस्ताव न्यायिक स्वास्थ्य, मानसिक लचीलेपन के मूल सिद्धांतों और न्यायिक स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

- इस दिन को न्यायिक कल्याण पर नाउरू घोषणा को अपनाने के साथ मेल खाने के लिए चुना गया था, जिसे मूल रूप से 25 जुलाई 2024 को एक क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन में पारित किया गया था।

- इस अनुष्ठान की जड़ें 23-25 जुलाई 2024 को अपनाए गए नाउरू घोषणापत्र में निहित हैं, जिसमें न्यायिक कल्याण पर वैश्विक स्तर पर चर्चा को सामान्य बनाने के उद्देश्य से सात मूल सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। नाउरू के न्यायमूर्ति रंगजीवा विमलसेना के नेतृत्व में, इस घोषणापत्र में न्यायिक तनाव—जिसे ऐतिहासिक रूप से वर्जित माना जाता है—पर खुली बातचीत का आह्वान किया गया और न्यायाधीशों के लिए भावनात्मक और मानसिक सहायता प्रणालियों हेतु नीतियों को बढ़ावा दिया गया।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसके पक्ष में 160 सदस्य देशों ने मतदान किया। इस प्रकार, यह न्यायपालिका पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दूसरा दिवस बन गया - पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस (10 मार्च) था। यह दिवस इस बात पर ज़ोर देता है कि स्वस्थ न्यायिक अधिकारी कानून के शासन को बनाए रखने और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

Key Points:-

(i) वैश्विक सर्वेक्षणों, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक न्यायिक अखंडता नेटवर्क द्वारा 2021-22 के अध्ययन, ने न्यायाधीशों में अत्यधिक तनाव का

खुलासा किया है। लगभग 92% ने नौकरी से संबंधित तनाव का अनुभव होने की बात कही, 76% ने कहा कि उनके पास व्यक्तिगत कल्याण के लिए पर्याप्त समय नहीं है, और 69% ने मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा को वर्जित माना। ये चिंताजनक आँकड़े दुनिया भर में न्यायिक अधिकारियों के समर्थन के लिए व्यवस्थित हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन (IBA) और संबंधित संगठनों ने 25 जुलाई 2025 को वेबिनार और पैनल चर्चाओं सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें "स्वास्थ्य और न्यायपालिका: वैश्विक परिप्रेक्ष्य" पर चर्चा की गई। न्यायिक नेताओं और विशेषज्ञों ने सामूहिक ज़िम्मेदारी की तात्कालिकता, समर्थन की माँग को कम करने और निरंतर अखंडता के लिए न्यायिक संस्थानों में कल्याण को समाहित करने पर ज़ोर दिया।

(iii) इस दिवस की स्थापना सतत विकास लक्ष्य 16 को भी सुदृढ़ करती है, जो समावेशी, जवाबदेह संस्थाओं और न्याय तक समान पहुँच को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर न्यायिक कल्याण का अवलोकन न्याय की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने, भ्रष्टाचार के जोखिमों को कम करने और न्यायालयों में जनता का विश्वास बढ़ाने का एक रणनीतिक साधन बन जाता है।

DEFENCE

1. भारत ने समुद्री पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दूसरा स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रचेत' लॉन्च किया।



23 जुलाई 2025 को, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में भारत के दूसरे स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत (PCV) 'समुद्र प्रचेत' का जलावतरण किया। यह जलावतरण भारत की समुद्री तेल रिसाव प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और आत्मनिर्भर भारत के तहत समुद्री रक्षा अवसंरचना में देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

- 4,170 टन वज़नी यह जहाज़ अत्याधुनिक तेल रिसाव नियंत्रण और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रणालियों से सुसज्जित है, जिनमें तेल नियंत्रण बूम, स्क़िम्मर, साइड-स्वीपिंग आर्म्स और डिस्पर्सेंट स्प्रे सिस्टम शामिल हैं। इसकी लंबाई 114.5 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर है, और इसे वास्तविक समय में प्रदूषण का पता लगाने, तेल की रिकवरी, जहाज़ पर प्रदूषकों को अलग करने और पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रियाओं का उपयोग करके निकाले गए तेल के सुरक्षित भंडारण जैसे जटिल कार्यों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- 72% स्वदेशी सामग्री के साथ, 'समुद्र प्रचेत' मेक इन इंडिया पहल का एक उदाहरण है, जिसमें भारतीय एमएसएमई और समुद्री प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। यह भारत के बढ़ते जहाज निर्माण क्षेत्र में स्थानीय रोजगार, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देता है। इस जहाज पर 14 अधिकारी और 115

नाविक तैनात हैं, जो महत्वपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में त्वरित तैनाती के लिए इसके चालक दल की परिचालन तत्परता को दर्शाता है।

- यह पोत 29 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित अपने सहयोगी पोत 'समुद्र प्रताप' का अनुवर्ती पोत है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ICG की जुड़वां PCV परियोजना को पूरा करता है। ये पोत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में, विशेष रूप से पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख बंदरगाहों के निकट, तेल रिसाव और रासायनिक रिसाव से निपटने की भारत की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे।

Key Points:-

(i) 'समुद्र प्रचेत' अग्निशमन, उच्च गति अवरोधन, पर्यावरण निगरानी और समुद्री कानून प्रवर्तन सहित द्वितीयक मिशनों के लिए भी सक्षम है।

(ii) 22 नॉट की अधिकतम गति, गतिशील पोजिशनिंग सिस्टम और लंबी दूरी की परिचालन क्षमता के साथ, यह पोत भारत की समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बहु-भूमिका वाला प्लेटफॉर्म है।

(iii) इस शुभारंभ समारोह में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस पोत की तैनाती भारत के समुद्री सुरक्षा ढाँचे में एक मील का पत्थर है, जो MARPOL कन्वेंशन (जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन) के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुरूप है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. NASA ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए TRACERS द्विन सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया।



जुलाई 2025 में, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने टैंडम रीकनेक्शन और कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनिसेंस सैटेलाइट्स (TRACERS) नामक एक नया अंतरिक्ष विज्ञान मिशन लॉन्च किया। इस दोहरे उपग्रह अभियान का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाली हानिकारक सौर हवा से ग्रह की कैसे रक्षा करता है।

- TRACERS अंतरिक्ष यान जोड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया।

- यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और तकनीकी प्रणालियों पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए NASA की रणनीतिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

- इस मिशन का नेतृत्व आयोवा विश्वविद्यालय (UI) के प्रमुख अन्वेषक डेविड माइल्स कर रहे हैं, जो टेक्सास के सैन एंटोनियो स्थित साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य ध्रुवीय कस्प पर चुंबकीय पुनर्संयोजन की घटनाओं की निगरानी करना है—एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सौर वायु के कण पृथ्वी के चुंबकीय आवरण को भेदते हैं।

(i) TRACERS उपग्रहों को बोइंग कंपनी द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया था, जिसे पहले मिलेनियम स्पेस सिस्टम्स के नाम से जाना जाता था। यह मिशन अंतरिक्ष प्लाज्मा अंतःक्रियाओं और चुंबकीय क्षेत्र व्यवहार के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-परिशुद्धता वाले, छोटे-उपग्रह प्लेटफ़ॉर्म में बोइंग के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है।

(ii) केवल 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ उड़ान भरते हुए, ये जुड़वां उपग्रह अपने एक साल के मिशन के दौरान 3,000 से ज़्यादा उच्च-रिज़ॉल्यूशन अवलोकन एकत्र करेंगे। ये माप सौर वायु को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडलों में योगदान मिलेगा।

(iii) TRACERS के साथ, फाल्कन 9 प्रक्षेपण में नासा के तीन अतिरिक्त पेलोड भी तैनात किए गए: एथेना ईपीआईसी (आर्थिक पेलोड एकीकरण लागत) स्मॉलसैट, तकनीकी प्रदर्शन के लिए पीईएक्सटी (बहुभाषी प्रायोगिक टर्मिनल), और रियल (सापेक्ष इलेक्ट्रॉन वायुमंडलीय हानि) क्यूबसैट। इन द्वितीयक मिशनों का उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में संचार, पेलोड एकीकरण और वायुमंडलीय कण हानि तकनीकों का परीक्षण करना है।

OBITUARY

1. प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में इम्फाल, मणिपुर में निधन हो गया।



पद्मश्री से सम्मानित और प्रख्यात भारतीय नाट्य निर्देशक रतन थियम का 23 जुलाई 2025 को 77 वर्ष की आयु में इम्फाल, मणिपुर में निधन हो गया। भारतीय रंगमंच में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाने जाने वाले, थियम शास्त्रीय और पारंपरिक विधाओं के सम्मिश्रण के माध्यम से आधुनिक भारतीय नाट्य अभिव्यक्ति को आकार देने में अग्रणी थे।

- 20 जनवरी 1948 को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में जन्मे रतन थियम ने 1976 में कोरस रिपोर्टरी थिएटर की स्थापना की, जो भारत में प्रयोगात्मक रंगमंच का एक प्रमुख केंद्र बन गया।

- रतन थियम ने 1987 से 1988 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) के निदेशक के रूप में कार्य किया और बाद में 2013 से 2017 तक NSD के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनके नेतृत्व में स्वदेशी रूपों का पुनरुद्धार और पारंपरिक सौंदर्यशास्त्र को मुख्यधारा के नाट्य प्रशिक्षण में एकीकृत किया गया।

- 1960 और 70 के दशक के दौरान थिएटर ऑफ़ रूट्स आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति, थियम ने कथकली, यक्षगान और छऊ जैसी भारतीय शास्त्रीय विधाओं को समकालीन विषयों के साथ मिलाकर एक विशिष्ट प्रदर्शन भाषा विकसित की। उनके काम का उद्देश्य आधुनिक भारतीय रंगमंच को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना था, और

प्रतीकात्मकता और अनुष्ठानिक कथावाचन से भरपूर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करना था।

Key Points:-

(i) उनके कुछ सर्वाधिक प्रशंसित नाटकों में धार्मिक भ्रष्टाचार की राजनीतिक आलोचना करने वाला लीमा येनलिंगई (1980); दुर्योधन के दुखद अंत पर आधारित संस्कृत रूपांतरण उरुभंगम (1981); और महाभारत युद्ध के बाद नैतिक पतन पर आधारित अंधायुग (1981) शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में चक्रव्यूह (1984), उत्तर प्रियदर्शी (1996), और ऋतुसंहारम (2002) शामिल हैं।

(ii) अपने करियर के दौरान, थियम को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 1989 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1997 में कालिदास सम्मान और भारतीय रंगमंच में उनके आजीवन योगदान के लिए 2012 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप (अकादमी रत्न) शामिल हैं।

(iii) उनके नाटकों का प्रदर्शन जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में किया गया, जिससे वे भारतीय रंगमंच के वैश्विक राजदूत के रूप में स्थापित हो गए।

Static GK

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)	अध्यक्ष: अजय सेठ	मुख्यालय: हैदराबाद
New Zealand	राजधानी: वेलिंग्टन	मुद्रा: न्यूज़ीलैंड डॉलर (\$) (NZD)
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)	केंद्रीय मंत्री: जयंत चौधरी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Maruti Suzuki India Limited	CEO : हिसाशी टेकुची	मुख्यालय: नई दिल्ली
Henley & Partners	CEO : डॉ. जुएर्ग स्टीफ़न	मुख्यालय : लंदन, यूनाइटेड किंगडम (UK)
SBI	अध्यक्ष: चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	मुख्यालय: मुंबई
PayPal Holdings, Inc.	CEO : एलेक्स क्रिस	अध्यक्ष: एलेक्स क्रिस
ADB	अध्यक्ष: मसातो	मुख्यालय: मंडालुयोंग शहर,

	कांडा	फिलीपींस
National Aeronautics and Space Administration (NASA)	कार्यवाहक प्रशासक : सीन पैट्रिक डफी	मुख्यालय : वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)